मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

आटे के दाम क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ गए हैं?	2
करनाल सहकारी शुगर मिल में भ्रष्टाचार	4
पूजा सिंघल से जुड़े मनरेगा घोटाले का मामला	5
कमजोर कांग्रेस एक राजनीतिक सच्चाई है, ठीकरा नेतृत्व के सिर पर...	6
सीवेज शोधन के तमाम प्लांट नाकारा केवल बिल बनाकर लूट कमाई के साधन बने	8

वर्ष 36 अंक 28 फरीदाबाद 22-28 मई 2022 फोन-8851091460 5.00 ₹

खेलने को मैदान तक नहीं, चले हैं सांसद खेल महोत्सव कराने

फ़रीदाबाद (म.मो.) खेलों के माध्यम से राजनीतिक प्रचार करने की नीयत से खट्टर सरकार ने हरियाणा के प्रत्येक ज़िले में सांसद खेल महोत्सव मनाने की प्रक्रिया 19 मई से शुरू कर दी है। इसके तहत यहां के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। इसमें ज़िले से भाजपाई सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर के अतिरिक्त तमाम विधायक व छुट-मुट नेता शामिल हुए। खेल समारोह के नाम पर जुटाई गई भीड़ के सामने खट्टर से लेकर मोदी तक का गुणगान किया गया।

उद्घाटन भाषणबाज़ी के बाद स्टेडियम में 1500 मीटर की दौड़ करा कर खेलों की शुरूआत कर दी गई। शेष तमाम खेल-कूद 20 तारीख को शुरू किये जाने की योजना है। इन तमाम खेलों को किसी एक जगह आयोजित कर पाने की कोई बड़ी जगह न होने के चलते, सरकार ने इसके लिये विभिन्न स्कूलों को पकड़ा है। बॉलीवॉल के लिये भोपानी गांव स्थित सतयुग दर्षण स्कूल, बैडमिंटन के लिये सेक्टर 14 स्थित मानव रचना तथा कुछ अन्य खेलों के लिये एनआईटी स्थित केएल मेहता महिला कॉलेज को लिया गया है। एथेलेटिक्स के तमाम इवेंट्स सेक्टर 12 खेल परिसर में ही रखे गये हैं।

इन खेलों में भाग लेने के लिये ज़िले भर की तमाम शिक्षण संस्थानों, खेल क्लबों व पंचायतों आदि अपनी-अपनी टीमें भेजने के लिये कहा गया है। इतना बड़ा समारोह सरकार आयोजित करे ओर उससे कोई कमाई न हो तो क्या फ़ायदा ऐसे धंधे का? लिहाज़ा खेलों में भाग लेने वालों के लिये अच्छी-खासी पंजीकरण फ़ीस लगा दी गई है।

व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ी को 200 रुपये देने होंगे। इतना ही नहीं यदि कोई खिलाड़ी 100 मीटर, 200 मीटर व 400 मीटर की दौड़ के साथ-साथ भाला फेंकने या लम्बी छलांग में भाग लेता है तो उसे हर प्रति स्पर्धा के लिये 200 रुपये खट्टर सरकार को देने होंगे। यानी कि कोई खिलाड़ी पांच स्पर्धाओं में भाग लेता है तो उसे हजार रुपये का टैक्स खट्टर सरकार को देना होगा। इसी प्रकार किसी खेल में भाग लेने वाली टीम को 500 रुपये का टैक्स अदा करना होगा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार

वॉलीबाल के लिये 24 टीमों ने पंजीकरण कराके 12000 रुपये सरकार को अदा कर दिये हैं। विदित है कि यह स्पर्धा सतयुग दर्षण स्कूल में होनी है जिसका पूरा खर्चा स्कूल स्वयं उठायेगा।

जो सरकार खेल परिसरों में अभ्यास करने को आने वाले खिलाड़ियों एवं सैर करने को आने वाले लोगों पर टैक्स लगा सकती है तो खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वालों से वसूली कैसे छोड़ सकती है? संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि 25 लाख के आबादी वाले इस शहर में युवाओं के खेलने के लिये पर्याप्त मैदान तक नहीं है। खेलने के लिये युवाओं को जगह-जगह बने निजी खेल मैदानों को भाड़े पर लेना पड़ता है। दो घंटे फुटबॉल खेलने के लिये युवाओं को 2 हजार रुपये तक का किराया देना पड़ता है। सारा दिन चलने वाले क्रिकेट जैसे खेल के लिये तो यह रकम 20 हजार से 50 हजार तक कुछ भी हो सकती है।

विदित है कि दिल्ली स्थित अनेकों बड़े खेल स्टेडियम मोदी सरकार ने पूंजीपतियों को पहले ही बेच रखे हैं। जो स्टेडियम के रख-रखाव के नाम पर खिलाड़ियों से अच्छी-खासी लूट कमाई करने में जुटे हैं।

यानी, खिलाड़ियों को खेल मैदान तक जो सरकार उपलब्ध न करा पाये वह बातें करती हैं ओलम्पिक मेडलों की। हां, जब कोई खिलाड़ी अपने संसाधनों के बल-बूते कोई अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत जाये तो उसकी सफ़लता को भुनाने मोदी जी तुरन्त टीवी पर प्रकट हो जाते हैं।

बरसती आग में खट्टर का खेल महोत्सव

48-50 डिग्री सेल्सियस में जब इंसान का घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं समझा जा रहा तो ऐसे मौसम में खट्टर को खेल महोत्सव मनाने की सनक सवार हो गई। वैसे अभी कहा नहीं जा सकता कि यह सनक बेचारे खट्टर की अपनी है या पार्टी हाई कमान द्वारा ऊपर से थोपी गई है। जिसकी भी यह सनक हो, लगता है उसकी अक्ल से अथवा जनता से पक्की दुश्मनी है।

दरअसल खेल-कूद का तो बहाना मात्र है, असल मकसद तो अधिक से अधिक युवाओं को भाजपा से जोड़ने के लिये इसे माध्यम बनाया गया है। समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों को देखा जाय तो हर जगह भाजपा के छोटे से बड़े पदाधिकारी छाये हुए हैं। खर्चा सरकार का यानी करदाता का और मशहूरी भाजपाईयों की। जो भी हो यह सब ड्रामेबाजी अक्टूबर-नवम्बर में, जब मौसम खुशनुमा होता है, कर ली जाती तो क्या हर्ज हो जाता? मौसम की खतरनाक मार को भांपते हुए सरकार ने खेल परिसरों में दो डॉक्टरों की नियुक्ति भी कर रखी है। लेकिन जब किसी पर 'हीट वेव' की गाज़ गिर ही जायेगी तो डॉक्टर बेचारे क्या कर पायेंगे? हाय रे खट्टर की मासूम समझदारी।

कमीशनखोरी के चलते बीके अस्पताल से साधारण डिलिवरी भी रैफ़र कर दी जाती हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर का प्रमुख सरकारी, 'बादशाहखान' अस्पताल, हरामखोरी व भ्रष्टाचार के चलते दिन ब दिन पतन की ओर अग्रसर होता जा रहा है। बेहद ग़रीब लोगों की मजबूरी है कि वे इलाज के लिये यहां आते हैं। जिसके जरा सा भी संसाधन हों वह यहां आकर राजी नहीं। इसी कड़ी में सेक्टर 8 निवासी पंकज अपनी पत्नी सोनिका को डिलिवरी के लिये 9 मई को प्रात: तीन बजे बल्लबगढ़ अस्पताल में पहुंचा तो वहां ड्यूटी डॉक्टर की बजाय किसी नर्स आदि ने उन्हें गंभीर मामला बता कर बीके अस्पताल रैफ़र कर दिया। साढे चार बजे बीके पहुंचे तो वहां भी डॉक्टर की बजाय किसी नर्स ने बताया कि गर्भस्थ शिशु की गर्दन पर ओडनाल लिपटी हुई है। मामला गंभीर है। मां बच्चे दोनों की जान खतरे में है। यहां इसकी डिलिवरी को भयंकर खतरा है। इतना डराने के बाद नर्स ने उसे सेक्टर 8 स्थित गोयल नर्सिंग होम का पता बताते हुए, सिफ़ारिश के तौर पर फ़ोन भी कर दिया। दरअसल फ़ोन सिफ़ारिश के लिये नहीं कमीशन के लिये किया गया था।

सुबह करीब 6 बजे ये लोग गोयल नर्सिंग होम पहुंचे तो वहां 40,000 रुपये मांगे गये जो इनके पास न थे। जैसे-तैसे जुगाड़ करके इन्होंने 10, 000 का इन्तजाम तो कर लिया परन्तु गोयल वाले 40 हजार से एक पैसा भी कम करने को तैयार न थे। मजबूरन इन लोगों को मुकेश कॉलोनी बल्लबगढ़ स्थित एक छोटे से क्लीनिक में आसरा मिला। वहां पहुंचते ही नार्मल डिलिवरी स्वत: ही हो गयी। क्लीनिक ने फ़ीस के तौर पर 11000 रुपये लिये। खट्टर सरकार, जहां दिन-रात अपनी पीठ थपथपाते हुए राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं का ढोल पीटते नहीं अघाती वहां एक साधारण डिलिवरी केस के लिये एक ग़रीब को 11000 खर्च करने पड़ गये और जो रात भर परेशानी में घूमते रहे, वह अलग। कहने को सरकार ने शहर में बड़े अस्पतालों के साथ-साथ अनेकों जगह डिलिवरी हट खोल रखे हैं लेकिन वे खुले कम और बंद अधिक रहते हैं।

पूरे मामले पर अस्पताल की प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉ. सविता यादव से उनका पक्ष जानने के लिये दो बार उनके दफ्तर में सम्पर्क करने का प्रयास किया तो वे वहां नहीं थीं। उनके फ़ोन नम्बर 7011511136 पर समपर्क करना चाहा तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जाहिर है कि जब पीएमओ का ऐसा रवैया हो तो समझा जा सकता है कि नीचे के कर्मचारी इस तरह के घपले क्यों नहीं करेंगे। दरअसल मातहत कर्मचारी इस तरह के घोटाले अपने उच्चाधिकारियों के संरक्षण व हिस्सा-पत्ती के बिना नहीं कर सकते।

इसके बाद जब सिविल सर्जन डॉ. विनय गुप्ता से इस मामले पर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही इस मामले की जांच करके अपना पक्ष रखेंगे। आगामी अंक में उनका पक्ष, जो भी होगा पाठकों के सामने रखा जायेगा।